रेलवे बोर्ड पुस्तकालय

१०१९. श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के पुस्तकालय में राजपत्रित और अराजपत्रित कितने पुस्तकाध्यक्ष काम करते हैं ;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं ; और

(ग) इन जातियों के कितने व्यक्ति वास्तव में काम पर लगे हुए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक पुस्तकाध्यक्ष (लायब्रेरियन) (राजपत्रित) एक सहायक पुस्तकाध्यक्ष (अराजपत्रित)

(ख) को नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

रेलवे बोर्ड पुस्तकालय

१०२०. श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के पुस्तकालय में पिछले दस वर्षों में कितनी बार पुस्तकों की संख्या की जांच-पड़ताल की गई ;

(ख) कितनी पुस्तकें खो गई या चोरी चली गई ; और

(ग) इससे सरकार को कितना नुक्सान हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेलवे बोर्ड के पुस्तकलय में हर दूसरे वर्ष पुस्तकों की जांच-पड़ताल की जाती है । इसके अलावा दिसम्बर १९६० और फिर जुलाई -अगस्त, १९६२ में विशेष जांच की गयी । विभागीय अफसर आकस्मिक जांच भी करते रहते हैं ।

(ख) अभी तक पुस्तकों के खो जाने या चुराये जाने की कोई घटना नोटिस में नहीं आयी है ।

(ग) ऊपर भाग 'ख' के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

Ports in Andhra Pradesh

1021. Shri E. Madhusudan Rao: Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ports of Kakinada, Masulipatnam and Krishnapatnam in Andhra Pradesh are being developed for the export of tobacco from Andhra Pradesh; and

(b) if so, the details thereof and the total cost of each projects?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). The executive responsibility for the development of Ports other than major Ports rests with the State Government. Details of steps being taken by the State Government for special facilities for the export of individual commodities, such as, tobacco are the concern of the State Government. Provision has, however, been included in the Central Third Five Year Plan for the general development of the three ports referred to as shown in the statement laid on table of the House. [Placed in Library, *See* No. LT-1578/63].